RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

# गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 247
दि. 07.01.2026, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


# बीच गेम्स से भारतीय खेलों को मिली नई उड़ान, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के लिए बताया टैलेंट का मंच

(जीएनएस)।

घोघला बीच पर सोमवार को खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण की रंगारंग शुरूआत हुई। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विशेष संदेश पढ़कर सुनाया गया। देशभर से आए 2100 से अधिक प्रतिभागियों की मौजूदगी वाले ये खेल 5 से 10 जनवरी तक आयोजित किए जा रहे हैं। दीव शहर खेलो इंडिया बीच गेम्स के रंग में रंगा हुआ है। खेलों का शुभंकर 'पर्ल' (खुशमिजाज और ऊजार्वान डॉलफि न) एथलीटों, सहयोगी स्टाफ, वॉलंटियर्स और केआईबीजी 2026 से जुड़े सभी हितधारकों का स्वागत कर रहा है।

**1100 से अधिक खिलाड़ी आठ खेलों में लेंगे हिस्सा**

केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव द्वारा आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल महासंघों के तकनीकी देखरेख में किया जा रहा है। इन खेलों में 1100 से अधिक खिलाड़ी आठ खेलों वॉलीबॉल, सॉकर, सेपक टकरॉ, कबड्डी, पेंकक सिलाट, ओपन वॉटर स्विमिंग, मल्लखंब और रस्साकशी में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनमें से पहले छह मैडल स्पोर्ट्स होंगे और कुल 32 स्वर्ण पदक दांव पर हैं।

खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए और केंद्र शासित प्रदेश को केआईबीजी 2026 की मेजबानी के लिए बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया बीच गेम्स का भारत के खेल परिदृश्य में विशेष स्थान है। समुद्र तट और तटीय खेल शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक दृढ़ता और लगातार बदलती परिस्थितियों में परफॉर्म करने की क्षमता की मांग करते हैं। उभरते हुए खेलों को मंच प्रदान कर ये खेल भारतीय खेलों के क्षितिज का विस्तार करते हैं और प्रतिभाओं की खोज, पहचान और उनको निखारने के लिए नए रास्ते खोलते हैं।

प्रधानमंत्री ने घोघला बीच को आयोजन स्थल के रूप में चुने जाने की सराहना करते हुए कहा, "ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच का चयन विशेष रूप से सराहनीय है। प्रकृति के साथ सामंजस्य में आयोजित खेल न केवल खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी सशक्त माध्यम बनते हैं। यह स्थल हमें याद दिलाता है कि उत्कृष्टता और सततता साथ-साथ आगे बढ़ती हैं।

खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने किया। इससे पहले एथलीटों की परेड और बीच गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चार खिलाड़ियों-डॉन रेमेडियोस (बीच फुटबॉल), पायल परमार (बीच वॉलीबॉल), अजीश पटेल और जलपा सोलंकी (दोनों रस्साकशी)-द्वारा पारंपरिक मशाल रिले आयोजित की गई। मशाल को श्री सिन्हा और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव एवं लक्षद्वीप के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल ने औपचारिक रूप से स्थापित किया।

श्री सिन्हा ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा,

"मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इसी घोघला बीच पर आयोजित पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पेंकक सिलाट में हमारे खिलाड़ियों ने कुल नौ पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया।"

उन्होंने आगे कहा, "2014 से अब तक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने दीव में उल्लेखनीय विकास कार्य किए हैं। इनमें आईएनएस खुकरी स्मारक का पुनर्विकास, घोघला बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन, और शहरी एवं ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। ये प्रयास सतत विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दशार्ते हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा, "आज भारत की खेल संस्कृति में गहरा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संस्थागत पहुंच, जमीनी स्तर पर भागीदारी और सांस्कृतिक बदलाव पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है, जिससे प्रतिभाओं की पहचान और सहयोग का स्वरूप बदल रहा है। आधुनिक बुनियादी ढांचा, वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धतियां और पारदर्शी प्रतियोगी मंच अब पृष्ठभूमि या भौगोलिक सीमाओं से परे युवा खिलाड़ियों तक पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कहा, "विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, हमारे युवा इस यात्रा के अग्रदूत हैं। खेल हो या विज्ञान, शिक्षा हो या प्रशासन, अंतरिक्ष हो या स्टार्ट-अप-हर क्षेत्र में अवसर बढ़े हैं। इससे ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है, जहां आकांक्षाओं के साथ संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित हो रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया, सांसद खेल महोत्सव और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) जैसी पहलें भारत के एथलीटों को वैश्विक प्रतिस्पधाओं और दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयार करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं।

## नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एफआईटीटी-आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

**सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेवएक्स ने प्रसारण और मनोरंजन क्षेत्र में मीडिया प्रौद्योगिकी उद्यमिता को गति देने हेतु ज्ञापन**

(जीएनएस)।

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्टअप एक्सेलेरेटर पहल वेवएक्स ने मीडिया, मनोरंजन, प्रसारण और संचार प्रौद्योगिकियों में नवाचार, इनक्यूबेशन और उद्यमिता को मजबूत करने के लिए फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफआईटीटी), आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू की उपस्थिति में नई दिल्ली के शास्त्री भवन में वेवएक्स और एफआईटीटी की टीमों ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस सहयोग के तहत, आईआईटी दिल्ली का एफआईटीटी वेवएक्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन और विस्तार में सहयोग करेगा। वेवएक्स कार्यक्रम एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना और उन्हें मजबूत बनाकर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। एफआईटीटी इनक्यूबेटर सेटअप के लिए रणनीतिक और परिचालन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करेगा, अन्य आईआईटी और नवाचार केंद्रों के साथ जुड़ाव को सुगम बनाएगा, तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान सुविधाओं, मेंटरशिप, बौद्धिक संपदा सहायता तक पहुंच प्रदान करेगा और स्टार्टअप्स और इनक्यूबेशन प्रबंधकों के लिए क्षमता निर्माण पहलों को सक्षम बनाएगा।

## राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने का आ'ान किया

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की गंभीर समस्याओं को देखते हुए दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। राजमार्ग प्राधिकरण ने अनुरोध किया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय राजमार्गों पर, विशेष रूप से नए और दूरस्थ क्षेत्रों में, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। जन सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं और राष्ट्रीय राजमार्गों के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, एनएचआई ने पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों पर

## सीएम योगी आदित्यनाथ 10 जनवरी को आयेंगे संगम

**माघ मेलाः सीएम योगी आदित्यनाथ 10 जनवरी को आयेंगे संगम, जांचेंगे स्नान पर्वों की तैयारियां, मौनी अमावस्या पर सबसे ज्यादा भीड़ होने की संभावना**

प्रयागराज। माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्वों मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी की तैयारियों की समीक्षा के लिए 10 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे।

वह गंगा पूजन करने के बाद संतों के शिविर में भी जाएंगे।माघ मेला तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हो गया है। संत और गृहस्थ कल्पवास में जुट गए हैं।

पहले स्नान पर्व पर 31 लाख श्रद्धालुओं के पावन संगम में डुबकी लगाने के बाद मेला प्रशासन को तीन प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री 10 जनवरी को आएंगे। वह गंगा पूजन करेंगे और फिर सतुआ बाबा के शिविर में जाएंगे।

**साधु-संतों से करेंगे मुलाकात**

वहां पर साधु-संतों से मुलाकात करेंगे। फिर मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार में 14-15 को मकर संक्रांति और 18 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या स्नान पर्व की तैयारी की समीक्षा बैठक करेंगे।

बैठक में मुख्य सचिव व डीजीपी के साथ ही विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव भी शामिल होंगे। मंडल तथा जिला स्तर और मेला पुलिस-प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शहर के भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू करा दी गई हैं।

## संक्षिप्त समाचार

### ट्रंप का 'कब्जा प्लान' लीक! वेनेजुएला के बाद इन 5 देशों पर चढ़ाई करेगी अमेरिकी सेना

वेनेजुएला में सफल सैन्य हस्तक्षेप और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, व्हाइट हाउस की नजरें अब दुनिया के पांच अन्य रणनीतिक ठिकानों पर हैं। ट्रंप का यह 'ग्रैंड एक्सपेंशन प्लान' ग्रीनलैंड के बफीर्ले क्षेत्रों से लेकर ईरान के तेल समृद्ध रेगिस्तानों तक फैला हुआ है। सैन्य शक्ति के बल पर वैश्विक सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की यह कोशिश अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मचा रही है। ट्रंप के इन कदमों से संकेत मिलता है कि अमेरिका अब केवल कूटनीति नहीं, बल्कि सीधे नियंत्रण की नीति पर चल रहा है।

## श्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिल, ओडिया, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और भारतीय सांकेतिक भाषाओं सहित शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में 55 साहित्यिक कृतियां जारी कीं

(जीएनएस)।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में 55 साहित्यिक कृतियां जारी कीं। इनमें भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की ओर से तैयार की गई 41 पुस्तकें, साथ ही केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) की ओर से लाई गई 13 पुस्तकें और एक तिरुक्कुरल सांकेतिक भाषा संग्रह शामिल हैं।

इस संग्रह में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया और तमिल भाषाओं में महत्वपूर्ण विद्वानों के काम शामिल हैं, साथ ही तिरुक्कुरल की भारतीय सांकेतिक भाषा में भी व्याख्या है। ये प्रकाशन भारत की भाषाई विरासत को शिक्षा और अनुसंधान के केंद्र में रखने और सांस्कृतिक गौरव को प्रोत्साहन देने के लिए एक बड़े राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा हैं, साथ ही शास्त्रीय ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ाव को भी सुदृढ़ करते हैं।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी भारतीय भाषाओं को सुदृढ़ करने और प्रोत्साहन देने के लिए बड़े पैमाने पर, जैसे कि शेड्यूल लिस्ट में और भाषाओं को शामिल करने, शास्त्रीय ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने और भारतीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन देने, का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय भाषाओं को खत्म करने के प्रयासों के बावजूद, वे समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और बहुत अधिक भाषाई विविधता वाला देश है, और यह समाज की जिम्मेदारी है कि देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को संरक्षित किया जाए और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि भाषाएं जोड़ने वाली शक्ति हैं और बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं।

श्री प्रधान ने यह भी कहा कि सांकेतिक भाषा में तिरुक्कुरल के सार को शामिल करना एक समावेशी भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करता है, जहां सभी के लिए ज्ञान तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है, और उन्होंने कहा कि यह प्रकाशन भारत के बौद्धिक साहित्य में एक मूल्यवान योगदान है।

उन्होंने आगे जोड़ा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय भाषाओं में शिक्षा के विजन को आगे बढ़ाती है, और भारत विविधता में एकता का एक जीवंत उदाहरण बना हुआ है, जहां भाषाएं समाज को जोड़ने का माध्यम हैं।

## नीति आयोग ने त्रैमासिक प्रकाशन 'ट्रेड वॉच क्वार्टरली' का पांचवां संस्करण जारी किया

(जीएनएस)।

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) के लिए 'ट्रेड वॉच क्वार्टरली' का नवीनतम संस्करण 6 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में नीति आयोग के सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी ने वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में जारी किया।

डॉ. अरविंद विरमानी ने कहा कि ट्रेड वॉच क्वार्टरली का नवीनतम संस्करण बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत के व्यापार प्रदर्शन का

व्यापक और आंकड़ों पर आधारित मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इसमें भारत के ऑटोमोटिव निर्यात की संरचना और प्रतिस्पर्धात्मकता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रकाशन में भारत के व्यापार स्वरूप में उभरते संरचनात्मक बदलावों का उल्लेख है, जिनमें प्रौद्योगिकी-प्रधान निर्यातों का बढ़ता योगदान, सेवा क्षेत्र समर्थित विकास में निरंतर मजबूत वृद्धि और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण दशार्ने वाले आयात संरचना में परिवर्तन शामिल हैं। इसके अलावा, यह त्रैमासिक अंक विषयगत खंड, भारत के ऑटोमोटिव निर्यात पर केंद्रित है। इसमें वैश्विक मांग का स्वरूप, वाहनों और ऑटो घटकों में भारत का निर्यात, टैरिफ संरचनाएं, अंतर-उद्योग व्यापार और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी का विश्लेषण दिया गया है और प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात बढ़ाने की प्रमुख चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं की पहचान की गई है।

## मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर शहर में टाइफाइड बीमारी फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति की सर्वग्राही समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की

**उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी वीडियो कॉन्फ्रेंस से सहभागी हुए**

**मुख्यमंत्री ने मरीजों के उपचार, रोग नियंत्रण व निवारण के लिए उठाए जा रहे कदमों को अधिक सघन बनाने के दिशानिर्देश दिए**

**गांधीनगर सहित राज्य के शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी के प्रतिदिन सैंपल लेकर उसकी योग्यता और क्लोरीनेशन की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही जल वितरण व्यवस्था हो : मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल**

**गांधीनगर महानगर पालिका द्वारा केसों की संख्या में उतरोत्तर कमी होने की जानकारी प्रदान की गई**

गांधीनगर, 06 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर में आयोजित उच्च स्तरीय सर्वग्राही समीक्षा बैठक में गांधीनगर शहर में टाइफाइड बीमारी फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति में महानगर पालिका तथा राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मरीजों के उपचार, रोग नियंत्रण तथा निवारण के लिए उठाए जा रहे कदमों को अधिक सघन बनाने के सुझाव दिए।

इस बैठक में गांधीनगर महानगर पालिका आयुक्त ने मुख्यमंत्री को इस बीमारी के नियंत्रण के लिए महानगर पालिका द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय में रहकर हो रहे कामकाज का विवरण देते हुए कहा कि अब केसों में उत्तररोत्तर कमी देखने को मिल रही है। महानगर पालिका द्वारा 85 सर्वे टीमें बनाकर 1 लाख 58 हजार से अधिक लोगों का सवेर्लांस किया गया है। क्लोरीन टैबलेट्स और ओआरएस पैकेट का भी पर्याप्त मात्रा में वितरण किया गया है। लीकेज के रिपेयरिंग कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है तथा सभी जल स्रोतों में सुपर क्लोरीनेशन भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जलजन्य बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सघन उपाय के रूप में गांधीनगर सहित राज्य के शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी के प्रतिदिन सैंपल लेकर उसकी योग्यता और क्लोरीनेशन की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही जल वितरण व्यवस्था करने के स्पष्ट दिशानिर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने वर्तमान में पाइपलाइन से संबंधित जो कार्य प्रगति पर हैं, उनकी फील्ड विजिट करके गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सुझाव दिए। उन्होंने वॉटर टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने और लीकेज को तत्काल प्रभाव से रोकने के कदम उठाने की ताकीद की।

इस बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तथा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजीव टोपनो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, जल आपूर्ति एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव श्री डॉ. विक्रांत पांडे, शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य कमिश्नर डॉ. रतनकंवर गढवीचारण, गांधीनगर महानगर पालिका आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे।

# सम्पादकीय

## 2026 और भारत की आर्थिक कहानी

2026 की दहलीज परः भारत की आर्थिक कहानी और वैश्विक भविष्य की तस्वीर साल 2025 से 2026 में कदम रखना केवल कैलेंडर का पन्ना पलटना भर नहीं है, बल्कि यह आत्ममूल्यांकन और नव-आरंभ का अवसर है। वास्तव में सच तो यह है कि यह समय उन सपनों और लक्ष्यों को फिर से साधने का है, जो बीते वर्ष परिस्थितियों, सीमाओं या संकोच के कारण अधूरे रह गए। साथ ही, यह आने वाली चुनौतियों को पहचानकर उनके लिए स्वयं को मानसिक, बौद्धिक और व्यवहारिक रूप से तैयार करने की प्रेरणा देता है। नया वर्ष हमें अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर आशा, संकल्प और सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। कोई भी साल पूरी तरह आदर्श नहीं होता, और 2025 भी इसका अपवाद नहीं रहा। हालांकि, उससे मिली सीख नए वर्ष में दिशा दिखा सकती है। बीता साल आर्थिक लिहाज़ से भारी उतार-चढ़ाव से भरा रहा। लंबी तेजी के बाद शेयर बाजार में सुस्ती आई, वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने के साथ टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। इन चुनौतियों के बीच भारत ने संतुलन और दृढ़ता का परिचय दिया। ट्रंप के दबाव के बावजूद रूस के साथ संबंधों को प्राथमिकता देकर भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। इसी अवधि में रूस, न्यूज़ीलैंड और ओमान के साथ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, जो भारत की वूटनीतिक सव्रियता और आत्मनिर्भर सोच को दशार्ते हैं। जीएसटी सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्थाः- जैसा कि पाठक जानते होंगे कि पिछले साल देश के भीतर जीएसटी 2.0 जैसे बड़े सुधार लागू किए गए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी खासी मजबूती मिली। इसका असर यह रहा कि दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि 8.2ट्ठ रही।साल के अंत तक भारत के जापान को पीछे छोड़कर लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान उसकी तेज़ और निरंतर आर्थिक वृद्धि पर आधारित है। कहना गलत नहीं होगा कि मजबूत घरेलू मांग, बढ़ता मध्यम वर्ग, सरकारी पूंजीगत खर्च, बुनियादी ढांचे में निवेश और जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधारों ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। साथ ही, वैश्विक सप्लाईं चेन में बदलाव और भारत को वैकल्पिक उत्पादन वेंद्र के रूप में मिल रहा भरोसा निवेश और निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। इसके विपरीत, जापान की अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि, घटती आबादी और सीमित घरेलू मांग से जूझ रही है। इन सभी कारणों के चलते भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है और मौजूदा अनुमानों के अनुसार वह वर्ष के अंत तक जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक आर्थिक रैंकिग में चौथे स्थान पर पहुंच सकता है।इसके अलावा, अन्य देशों के साथ हुईं व्यापार संधियाँ और अमेरिका के साथ होने वाला समझौता पूरा होने से आगे चलकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियों और अनिातिताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने की संभावना है। इसका मुख्य कारण देश के भीतर मजबूत मांग, महंगाई का नियंत्रण में रहना और सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुलित आर्थिक नीतियां हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में 2030 तक जर्मनी को पछाड़ देगा भारतः- अनुमान है कि भारत 2030 तक जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशत्ति बन जाएगा। सरकार ने भरोसा जताया है कि मजबूत आर्थिक नींव के साथ, भारत की जीडीपी 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अच्छी स्थिति में हैं, उनके पास पर्याप्त पूंजी और नकदी भंडार है, खराब कर्ज में कमी आई है और उनका मुनाफा भी मजबूत बना हुआ है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि वेंद्रीय बैंक के दबाव परीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्रतिवूल हालात में भी बैंक संभावित नुकसान सहन कर सकते हैं और उनकी पूंजी नियामकीय न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर रहेगी।

# सारस-2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में होगा

**स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों, नए उत्पाद अवसरों और आधुनिक विपणन रणनीतियों को समझने का यह अनूठा अवसर होगाः डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी**

**यह मेला आंध्र प्रदेश की महिला एवं बाल विकास एजेंसी डीडब्ल्यूसीआरए (ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास) के अंतर्गत आने वाली महिलाओं का महत्वपूर्ण मंच है: डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी**

**सारसझ2026 में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 300 महिला कारीगर और उद्यमी एक साथ आएंगी**

(जीएनएस)। ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मीडिया को सारस मेला 2026 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 6 से 18 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित सारस मेला आयोजित किया जाएगा जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने बताया कि इस मेले में देश के सभी राज्यों के महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अपनी शिल्पकारी और उद्यमशीलता का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आएंगे।

मेले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि यह मेला आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास (डीडब्ल्यूसीआरए) से जुड़ी महिलाओं का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए यह मेला राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों को समझने, नए उत्पाद विकल्पों का पता लगाने और अपने व्यवसायों को बढ़ाने में मददगार आधुनिक विपणन रणनीतियों को सीखने का एक अनूठा अवसर है।

राष्ट्रीय स्तर की इस 13 दिवसीय प्रतिष्ठित सारसझ2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 8 जनवरी 2026 की शाम 4:00 बजे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। इस अवसर पर संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी चंद्रशेखर उपस्थिति रहेंगे।

पहली बार गुंटूर में इतने बड़े पैमाने पर किसी आयोजन की मेजबानी की जा रही है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका पहल को जिले में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 13 दिनों तक चलने वाले इस मेले में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

सारस मेला एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्थायी आजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है । इस मेले में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 300 महिला कारीगर और उद्यमी भाग लेंगी , जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी।

इस मेला में बांस से बने उत्पादों, पोचमपल्ली एवं गडवाल बुनाई जैसे हथकरघा और वस्त्रों, पारंपरिक आभूषणों, हस्तशिल्प, गृह सज्जा की वस्तुओं, जूट और पर्यावरण के अनुकूल अन्य उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के प्रामाणिक हस्तनिर्मित उत्पादों के माध्यम से देश की समृद्ध सांस्कृतिक और शिल्प विविधता प्रदर्शित की जाएगी। आगंतुक अखिल भारतीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) फूड कोर्ट में देश के समृद्ध खान-पान का भी आनंद ले सकेंगे। मेले में रायलसीमा व्यंजन, मदुगुला हलवा, भीमिली थंद्रा और अत्रेयपुरम पूथारेकुलु जैसे क्षेत्रीय व्यंजन परोसे जाएंगे।

मेले में हर शाम सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें बच्चों के लिए विशेष आकर्षण होंगे। इस कार्यक्रम में अंतर-राज्यीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी ।

इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के लिए प्रमुख आजीविका विषयों पर विशेषज्ञ संरचित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। एक समर्पित लखपति दीदी पवेलियन में महिला उद्यमियों की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें जिलेवार भागीदारी और विविध आजीविका गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी।

सुरक्षा और मेले का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल पर 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से 247 निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही तीन कार्यालय पालियों (शिफ्टों) में चौबीसों घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान, इसमें भाग लेने वाले स्वयं

# लेबर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और मोदी सरकार के कर्मचारी-अनुकूल दृष्टिकोण की सराहना की

**पेंशनभोगी समूहों ने डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की, सर्विस और पेंशन संबंधी मामलों पर निरंतर बातचीत जारी रखने की मांग की**

**केंद्रीय मंत्री ने पेंशनभोगियों की समस्याओं को सुना, पेंशनभोगी समूहों को स्वीकार्य और परामर्शपूर्ण दृष्टिकोण का आश्वासन दिया**

(जीएनएस)। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से जुड़े प्रमुख टेलीकॉम और पोस्टल पेंशनर्स संगठनों के पदाधिकारियों ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से कर्तव्य भवन स्थित डीओपीटी मुख्यालय में मुलाकात की तथा सर्विस, रोजगार और पेंशन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही सरकार के कर्मचारी-अनुकूल दृष्टिकोण की सराहना भी की।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि वे "सरकार की उन नीतियों की अत्यधिक सराहना करते हैं, जो कर्मचारियों के हित में हैं," और उन्होंने पेंशनभोगियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों पर उनके विचार भी जाने। उन्होंने यह भी बताया कि चर्चा में सर्विस, रोजगार और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर बात हुई, और इस बात पर सहमित बनी कि सरकार आमतौर पर ऐसी बातों को सुनने के लिए तैयार रहती है और यह बातचीत जारी रहनी चाहिए।

इस बातचीत में भारतीय दूरसंचार पेंशनर्स संघ, भारतीय पोस्टल पेंशनर्स संघ और अन्य संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने टेलीकॉम और पोस्टल सेक्टर के पेंशनभोगियों से जुड़े मुद्दों को उठाया। प्रतिभागियों ने कहा कि चर्चा में स्पष्टता, समय पर जानकारी के आदान-प्रदान और पेंशनभोगियों के संगठनों एवं संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर ध्यान केंद्रित किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने सुझावों को सुना और हितधारक समूहों (खासकर सेवानिवृत्त लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर) के साथ नियमित रूप से बातचीत के महत्व को दोहराया। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स की संस्थाओं से मिलने वाली जानकारी जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं उत्तरदायी बनी रहें।

प्रतिनिधियों ने पेंशन प्रशासन से संबंधित कुछ व्यक्तिगत और संगठनात्मक मामले भी उठाए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ध्यान देने की मांग की कि सेवानिवृत्त लोगों को बेवजह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बैठक में शामिल लोगों ने बताया कि बैठक का माहौल सकारात्मक और भविष्योन्मुखी रहा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बातचीत को सरकार और कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के संगठनों के बीच चल रही परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा बताया, तथा सेवा और पेंशन से जुड़े मामलों पर निरंतर बातचीत के महत्व पर जोर दिया।

इस बैठक में उपस्थित लोगों में भारतीय दूरसंचार पेंशनर्स संघ के अखिल भारतीय महासचिव श्री हरि विनायक सोवानी; एमटीएनएल के पूर्व कर्मचारी श्री धर्मराज; बीटीईयू (बीएसएनएल) के महासचिव श्री आर.सी. पांडे; एआईजीईटीओए के महासचिव श्री रविशील वर्मा; भारतीय पोस्टल पेंशनर्स संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री शशिकांत कुलकर्णी; बीपीपीएस के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष श्री जे.पी. माली; बीपीईएफ के पूर्व संगठन सचिव संतोष कुमार सिंह; और बीपीईएफ के महासचिव श्री अनंत कुमार पाल शामिल थे।

# सहकार से समृद्धि : 6 जुलाई, 2021 को एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना

(जीएनएस)। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई, 2021 को एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मंत्रालय ने सहकारिता क्षेत्र को सशक्त और जीवंत बनाने के लिए विभिन्न पहल और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 4 साल में 114 प्रमुख पहलों को क्रियान्वित किया है, जिससे देश भर में सहकारी समितियों के आर्थिक विकास और विस्तार के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। इन पहलों पर विवरण एवं इन पर अब तक हुई प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैं:

(क)प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण

1. पैक्स को बहु-उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उपविधियां

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मानना है कि पैक्स जब बहु-उद्देशीय होंगी तभी वो और अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से व्यवहार्य होंगी ' इसके लिए उनके नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय संघो एवं अन्य हितधारकों से परामर्श के पश्चात तैयार की गई एवं 05 जनवरी 2023 को परिचालित की गई '

इससे ढअउर/ छअटढर की आय के स्रोत बढ़ेंगे और लगभग 25 से अधिक नए क्षेत्रों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, भण्डारण, इत्यादि में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे '

अब तक, 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आदर्श उपविधियों को अपना लिया है या उनकी मौजूदा उपविधियां आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं।

2.पैक्स के सशक्तिकरण हेतु उनका कम्प्यूटरीकरण

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (ढअउर) का कंप्यूटरीकरण एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे 29 जून 2022 को अनुमोदित किया गया, जिसका उद्देश्य 31 मार्च 2027 तक ढअउर को डिजिटल रूप से सक्षम संस्थानों में परिवर्तित करना है।

प्रारंभ में 63,000 ढअउर के लिए ₹2,516 करोड़ की लागत के साथ स्वीकृत इस परियोजना का विस्तार 79,630 ढअउर तक किया गया है, और कुल बजट को संशोधित कर ₹2,925.39 करोड़ कर दिया गया है।

यह परियोजना भारत सरकार, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित हैः

भारत सरकारः ₹1,796.28 करोड़ (पूर्व में ₹1,528 करोड़)

राज्य/केंद्रशासित प्रदेशः ₹877.11 करोड़ (पूर्व में ₹736 करोड़)

नाबार्डः ₹252 करोड़

वर्तमान तिथि तक, भारत सरकार ने ₹1,067.50 करोड़ जारी किए हैं, जिनमें से ₹901.58 करोड़ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को हार्डवेयर की खरीद, डिजिटाइजेशन और सहायक प्रणालियों के लिए जारी किए गए हैं, तथा ₹165.92 करोड़ नाबार्ड को दिए गए हैं, जो कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सॉफ्टवेयर विकास, क्लाउड डेटा भंडारण, साइबर सुरक्षा, प्रशिक्षण और परियोजना प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस बात पर बल दिया है कि यह परियोजना पैक्स के कार्यकरण में पारदर्शिता बढ़ाएगी और सहकारी प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगी।

प्रगति के संदर्भ में, वर्तमान स्थिति के अनुसार 59,261 पैक्स सक्रिय रूप से सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, जबकि 2 जनवरी 2025 तक यह संख्या 47,155 पैक्स थी। हार्डवेयर 65,151 पैक्स तक पहुंचाया जा चुका है, जो 79,630 पैक्स के विस्तारित लक्ष्य का लगभग 82% है (जबकि जनवरी 2025 तक 57,578 पैक्स कवर किए गए थे)। 2025 से कुछ नए मानकों को ट्रैक किया जा रहा है, जैसे कि प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन ऑडिट, जो 42,730 पैक्स में पूरे किए जा चुके हैं।

# आईबीबीआई अध्यक्ष ने आईआईसीए पीजीआईपी प्रोग्राम की वेबसाइट लांच की

(जीएनएस)। भारतीय दिवालियापन एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) के अध्यक्ष श्री रवि मित्तल ने सोमवार को परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) के पीजीआईपी कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

आईबीबीआई अध्यक्ष ने छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें मजबूत संस्थागत समर्थन का आश्वासन दिया और घोषणा की कि कुछ चयनित पीजीआईपी छात्रों के लिए आईबीबीआई में एक वर्ष की इंटर्नशिप के अवसर सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि शोध कार्यकलापों में रुचि रखने वाले छात्र आगामी आईबीबीआई शोध कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर उन्हें आईबीबीआई के छात्रों की सूची में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

वेबसाइट लॉन्च कार्यक्रम में स्वागत भाषण आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने दिया, जिन्होंने क्षमता निर्माण, अकादमिक उत्कृष्टता और नियामकों तथा उद्योग के साथ घनिष्ठ जुड़ाव के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता रेखांकित की।

इस कार्यक्रम के दौरान, आईआईसीए के दिवालियापन और दिवालिया केंद्र के विभागाध्यक्ष श्री सुधाकर शुक्ला ने पीजीआईपी केंद्र की गतिविधियों और उपलब्धियों का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें इसकी अकादमिक कठोरता, उद्योग के साथ संबंध और पूर्व छात्र के बढ़ते नेटवर्क की रूपरेखा शामिल थी।

यह वेबसाइट पीजीआईपी के पूर्व छात्रों को वर्तमान छात्रों से जोड़ने के लिए बनाया गया एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पूर्व छात्रों की सहभागिता के माध्यम से छात्रों के लिए निरंतर संवाद, ज्ञान साझाकरण, समस्या-समाधान और उद्योग जगत के साथ बेहतर संपर्क में सक्षम बनाएगा।

छात्रों ने एक संवादमूलक सत्र के दौरान आईआईसीए के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान सम्मेलनों, सेमिनारों में भाग लेने और उद्योग विशेषज्ञों के साथ सार्थक बातचीत के अवसरों का उल्लेख किया गया, जिसने उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक यात्रा को अत्यधिक समृद्ध किया।

# संयुक्त रूप से तीसरी तकनीकी हिंदी संगोष्ठी का आयोजन

**सी एस आई आर - एन आई एस सी पी आर, आई आई टी इंदौर और आई आई टी जोधपुर ने संयुक्त रूप से तीसरी तकनीकी हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया**

(जीएनएस)। तीसरी तकनीकी हिंदी संगोष्ठी 'अभ्युदय-3' का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई आई टी) इंदौर में आयोजन किया गया। आज इस दो दिवसीय संगोष्ठी का समापन हुआ। इस संगोष्ठी का आयोजन संयुक्त रूप से आई आई टी इंदौर, आई आई टी जोधपुर और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान (सी एस आई आर झ एन आई एस सी पी आर) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस संगोष्ठी का उद्देश्य तकनीकी हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना और समाज के व्यापक वर्गों तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहुँच को मजबूत करना है।

उद्घाटन सत्र में, संगोष्ठी स्मारिका और अन्य प्रकाशन जारी किए गए। आई आई टी इंदौर के निदेशक ने तकनीकी हिंदी के महत्व, प्रभावी विज्ञान संचार की भूमिका और अनुसंधान और नवाचार को आम जनता से जोड़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सी एस आई आर झ एन आई एस सी पी आर के मुख्य वैज्ञानिक श्री सी. बी. सिंह ने तकनीकी हिंदी के विकास, प्रभावी विज्ञान संचार के महत्व और अनुसंधान एवं नवाचार को समाज के बड़े तबकों तक ले जाने की आवश्यकता पर बाल दिया। उन्होंने हिंदी भाषा में वैज्ञानिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में सी एस आई आर झ एन आई एस सी पी आर के योगदान और लगातार प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें 1952 से लोकप्रिय हिंदी विज्ञान पत्रिका "विज्ञान प्रगति" का प्रकाशन भी शामिल है।

श्री सिंह ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बीच एक सशक्त सेतु बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, और वैज्ञानिक विचारों को आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाने का एक प्रभावशाली माध्यम बनते हैं।

संगोष्ठी में विज्ञान, अभियांत्रिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा वक्तव्य दिए गए। दो सत्र, पत्र प्रस्तुति के भी हुए, जिसमें 25 प्रतिभागियों ने हिंदी भाषा में अपने अनुसंधान और विचार साझा किए।

# तारकीय जुड़वाँ (स्टेलर ट्विन्स) के अध्ययन ने तारों के विकास और उनके भविष्य के रहस्यों से उठाया पर्दा

(जीएनएस)। एक प्रकार के तारकीय जुड़वाँ, जिन्हें डब्ल्यू उर्से मेजोरिस प्रकार संपर्क द्वितारा कहा जाता है और जो एक-दूसरे की बहुत करीबी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, इनके अध्ययन से द्वितारा (बाइनरी) तारों के विकास और उनके अंतिम परिणाम के बारे में नए दृष्टिकोण प्राप्त हुए हैं।

डब्ल्यू उर्से मेजोरिस तारे अल्प-अवधि वाले, डम्बल आकार के द्वितारा तंत्र होते हैं जिनमें दोनों तारे एक-दूसरे के संपर्क में होते हैं। वे इतने करीब होते हैं कि वे एक ही बाहरी वायुमंडल साझा करते हैं और एक-दूसरे की परिक्रमा करते रहते हैं। ये तारे "प्राकृतिक प्रयोगशालाओं" की तरह काम करते हैं, क्योंकि वे द्रव्यमान, त्रिज्या और तापमान जैसे मौलिक तारकीय मापदंडों के सटीक निर्धारण में मदद करते हैं, जो यह जाँचने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कि समय के साथ तारे कैसे विकसित होते हैं।

आर्यभट प्रेक्षणीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान (एरीज) के खगोलविदों ने, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, तथा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर, एरीज के 1.3 मीटर देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप (डीएफओटी) और नासा के टेस आँकड़ों का उपयोग कर इन तारों की विस्तृत प्रकाश-वक्र (लाइट कर्व) तैयार की। यह

प्रकाश-वक्र मूलतः दशार्ती हैं कि समय के साथ इस तंत्र से उत्सर्जित कुल प्रकाश की मात्रा किस प्रकार बदलती है?

एरीज के योगेश चंद्र जोशी और पीआरएल के अलेक्जेंडर पंचाल के नेतृत्व वाली टीम ने चार डब्ल्यू उर्से मेजोरिस-प्रकार (ह वटं) संपर्क तारों का अध्ययन किया। उनके अध्ययन से तारों की कक्षाओं में बदलाव, तारों के बीच द्रव्यमान हस्तांतरण और सतह पर गतिविधि जैसे स्टार स्पॉट्स के प्रमाण जैसे महत्वपूर्ण पहलू सामने

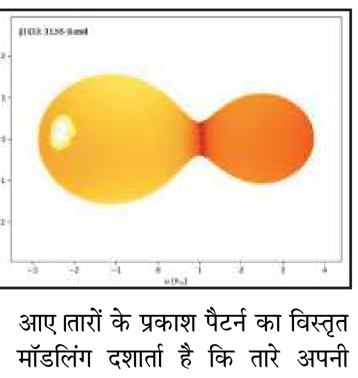

आए।तारों के प्रकाश पैटर्न का विस्तृत मॉडलिंग दशार्ता है कि तारे अपनी बाहरी परतें साझा करते हैं, उनकी कक्षाएँ समय के साथ थोड़ी बदलती हैं मानो वे एक-दूसरे को खींच रहे हों, और कुछ तारे असमान दिखते हैं— एक तरफ दूसरे से अधिक चमकीले।

येअसमान चमक गहरे चुंबकीय स्टार स्पॉट्स की ओर इशारा करती है, जो सूर्य के धब्बों जैसी होती हैं। ये स्पॉट्स घूमते हुए नजर में आते-जाते हैं, जिससे प्रकाश-वक्र में उभार बनते हैं। इससे पता चलता है कि तारों में मजबूत चुंबकीय गतिविधि है। एक द्वितारा तंत्र में वैज्ञानिकों को एच-आल्फा और एच-बीटा जैसे विशिष्ट प्रकाश संकेत भी मिले, जो तारे की बाहरी परत में इस गतिविधि को साफ दिखाते हैं, जो स्टार स्पॉट्स और तारकीय ज्वलनों जैसी चुंबकीय घटनाओं से जुड़े है।

सर्वोत्तम फोटोमेट्रिक निगरानी को प्रकाश हस्ताक्षरों (स्पेक्ट्रल डायग्नोस्टिक्स) के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन ने न केवल द्विआधारी तारों के विकास और उनके अंतिम भाग्य के बारे में नई जानकारियां प्रदान कीं, बल्कि निम्न-द्रव्यमान तारों के द्रव्यमान-त्रिज्या संबंध की अनुभवजन्य कैलिब्रेशन की हमारी समझ को बेहतर बनाने में भी मदद की। यह शोध महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी अनुप्रयोग हैं, विशेष रूप से एक्सोप्लैनेट ट्रांजिट अध्ययनों में।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

# 'श्रमिकों को हफ्ते में भुगतान किया जाएगा', सीएम योगी ने G-RAM-G की गिनाई खूबियां, कहा- भुगतान में देरी हुई तो मुआवजा मिलेगा

'श्रमिकों को हफ्ते में भुगतान किया जाएगाङ्ग', CM योगी ने G-RAM- की गिनाई खूबियां, कहा- भुगतान में देरी हुई तो मुआवजा मिलेगा

(जीएनएस)।

लखनऊ। साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने पीएम मोदी की जीरामजी की खूबी गिनाई। उन्होंने कहा कि देश की आधारभूत इकाई, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि विकसित भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सके। विकसित भारत- रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण 2025 पारित हो गया है। पहले मजदूरी देने में भ्रष्टाचार होता था। हमने किसानों, मजदूरों का हित सुरक्षित किया।

गांवों में तेजी से विकास हो रहा

सीएम योगी ने कहा कि जीरामजी मील का पत्थर साबित होगा। देश के संसाधनों के डकैतों ने विरोध किया।

पोल ना खुल जाए इसलिए जीरामजी का विरोध है। यूपी में गांव में तेजी से विकास हो रहा है। यूपी में गांव में तेजी से विकास हो रहा है। ऋ्र-फ्ऊट-ऋ्र से गांव-गांव विकास होगा। कांग्रेस ने संसाधनों पर डाका डाला था। ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगा। विपक्ष रोजगार सृजन में विफल रहा है। हम 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रहे। विपक्ष अधिनियम पर सवाल उठा रहा है। श्रमिकों को हफ्ते में भुगतान किया जाएगा। भुगतान में देरी हुई तो मुआवजा मिलेगा।

फ्एअऊटडफ्ए: योगी कैबिनेट की बैठक आजः कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा, नए साल में प्रदेशवासियों को मिलेगा तोहफा

विपक्ष पर साधा जमकर निशाना

सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वह लोग जिन्होंने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है। देश के गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया है। ऐसे सुधारों का समर्थन करने की बजाय उनका क्ठऊक्र गठबंधन इस महत्वपूर्ण कानून को लेकर कई सवाल उठा रहा है। जबकि देश, किसानों, मजदूरों और गांवों के विकास के हित में उठाए गए कदमों का समर्थन किया जाना चाहिए लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की अपनी पुरानी परंपराओं का समर्थन कर रहा है।

# उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रख्यात जननेता स्व. कल्याण सिंह जी की 94वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रख्यात जननेता स्व. कल्याण सिंह जी की 94वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थान के निदेशक प्रो.एम.एल.बी.भट्ट जी नें किया । उन्होने अपने सम्बोधन में कहा कि स्व. कल्याण सिंह जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, सामाजिक समरसता, सुशासन एवं जनकल्याण को समर्पित रहा। उन्होंने सदैव आमजन, विशेषकर समाज के अंतिम

पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य किया। उनके द्वारा स्थापित मूल्यों और सिद्धांतों पर चलकर ही समाज एवं संस्थानों का सर्वांगीण विकास संभव है।

कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. विजेंद्र, चिकित्सा अधीक्षक डा. वरुण विजय, रजिस्ट्रार डा. आयुष लोहिया, डा. प्रमोद कुमार गुप्ता, डा.एस. प्रिया, डा. अंजू, डा.रूचि, डा. अभिनव, डा. शिल्पी एवं डा.राखी के साथ संस्थान के रेसिडेंट्स, नर्सिंग अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सभी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की तथा उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।

# श्रद्धा, मनोरंजन व रोजगार का संगम है गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला

**मकर संक्रांति से शुरू होकर माहभर से अधिक चलने वाले मेले की तैयारियां पूरी**

**त्रेतायुगीन है महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा**

गोरखपुर, 6 जनवरी। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने और इससे पखवारा पूर्व शुरू होकर माह भर से अधिक समय तक चलने वाला खिचड़ी मेला श्रद्धा, मनोरंजन और रोजगार का संगम है। पूरी प्रकृति को ऊर्जस्वित करने वाले सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की अनूठी परंपरा पूरी तरह लोक को समर्पित है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाए जाने वाला अन्न वर्षभर जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है। मंदिर के अन्न क्षेत्र में कभी भी कोई जरूरतमंद पहुंचा, खाली हाथ नहीं लौटा। ठीक वैसे ही, जैसे बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगने वाला कभी निराश नहीं होता। मंदिर में खिचड़ी का यह पर्व इस वर्ष 15 जनवरी को मनेगा।

गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेतायुगीन मानी जाती है। मान्यता है कि तत्समय आदियोगी गुरु गोरखनाथ एक बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार मे पहुंचे। मां ने उनके भोजन का प्रबंध किया। कई प्रकार के व्यंजन देख बाबा ने कहा कि वह तो योगी हैं और भिक्षा में प्राप्त चीजों को ही भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने मां ज्वाला देवी से पानी गर्म करने का अनुरोध किया और स्वयं भिक्षाटन को निकल गए। भिक्षा मांगते हुए वह गोरखपुर आ पहुंचे और राप्ती और रोहिन के तट पर जंगलों में बसे इस स्थान पर धूनी रमाकर साधनालीन हो गए। उनका तेज देख लोग उनके खप्पर में अन्न (चावल, दाल) दान करते रहे। मकर संक्रांति का पर्व आने पर यह परंपरा खिचड़ी पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का क्रम हर मकर संक्रांति पर अहर्निश जारी है। कहा जाता है कि उधर ज्वाला देवी के दरबार मे बाबा की खिचड़ी पकाने के लिए आज भी पानी उबल रहा है।

मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरानुसार गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगलकामना करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु शिवावतारी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भोर में सबसे पहले गोरक्षपीठ की तरफ से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित करते हैं। तत्पश्चात नेपाल राजपरिवार की ओर से आई खिचड़ी बाबा को चढ़ाई जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और जनसामान्य की आस्था खिचड़ी के रूप में निवेदित होनी शुरू हो जाती है। खिचड़ी महापर्व को लेकर मंदिर व मेला परिसर सज धजकर तैयार है। प्रशासन के साथ ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी अब तक तीन बार खिचड़ी मेला की तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं।

सामाजिक समरसता का केंद्र है गोरखनाथ मंदिर

गोरखनाथ मंदिर सामाजिक समरसता का ऐसा केंद्र है जहां जाति, पंथ, महजब की बेड़ियां टूटती नजर आती हैं। इसके परिसर में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबकी दुकानें हैं। यानी बिना भेदभाव सबकी रोजी रोटी का इंतजाम है। यही नहीं, मंदिर परिसर में लगने वाला खिचड़ी मेला भी जाति-धर्म के बंटवारे से इतर हजारों लोगों की आजीविका का माध्यम बनता है। मंदिर परिसर में नियमित रोजगार करने वालों से लेकर मेला में दुकान लगाने वालों तक, बड़ी भागीदारी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की होती है। उन्होंने कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं किया बल्कि अपनेपन के भाव से विभोर होते रहते हैं। मेले में खरीदारी से लेकर मनोरंजन के साधनों तक का भरपूर इंतजाम हैं।

# यूपी कौशल विकास मिशन की शानदार सफलताः योगी सरकार ने लाखों युवाओं को बनाया आत्मनिर्भर, 2026 में 5 मंडलों में मेले—1 लाख नौकरियां मिलने की उम्मीद

**यूपी कौशल विकास मिशन रोजगार मेले 2026**

**उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन से युवाओं को रोजगार।**

लखनऊ, (जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत इच्छाशक्ति से महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और युवा रोजगार जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन अब प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम बन चुका है। यह मिशन न केवल कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, बल्कि उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़कर युवाओं को सीधे रोजगार दिला रहा है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने गर्व से बताया कि योगी सरकार का स्पष्ट विजन है—स्थानीय स्तर पर रोजगार देकर पलायन रोकना और उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना।

यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। योगी सरकार ने कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों की मांग से जोड़कर एक समन्वित मॉडल विकसित किया है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अद्भुत भूमिका निभा रहा है। 2026 की शुरूआत में प्रदेश के 5 जनपदों में मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेले आयोजित होने जा रहे हैं। इन मेलों में औसतन 100 निजी कंपनियां भाग लेंगी और प्रत्येक मेले में 20 हजार युवाओं को मौके पर ही रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर एक लाख युवाओं को नौकरी देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। ये मेले संबंधित मंडलों के कई जनपदों के युवाओं के लिए खुले होंगे, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे।

2017 से अब तक की शानदार यात्राः लाखों युवाओं की जिंदगी बदली

योगी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से कौशल विकास मिशन ने गजब की रफ्तार पकड़ी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक जनपद और मंडल स्तर पर 186 वृहद रोजगार मेले आयोजित किए गए। इन मेलों के माध्यम से 4.32 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। यह आंकड़ा किसी भी सरकार की रोजगारपरक नीतियों की सबसे बड़ी सफलता को दशार्ता है। युवा अब घर बैठे नहीं, बल्कि कौशल से सशक्त होकर नौकरी पा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस करते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 1,624 रोजगार मेले आयोजित हुए। इनसे 2.26 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिला। यह योजना गांवों के युवाओं को शहरों की ओर पलायन करने से रोक रही है और स्थानीय स्तर पर ही सम्मानजनक आजीविका प्रदान कर रही है।

कोविड महामारी के कठिन दौर में जब ऑफलाइन गतिविधियां ठप थीं, तब भी योगी सरकार ने हार नहीं मानी। ऑनलाइन रोजगार मेलों के जरिए 10,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां दिलाई गईं। यह दृढ़ संकल्प और नवाचारी सोच का बेहतरीन उदाहरण है।

चालू वित्तीय वर्ष में विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रदेश के 74 जनपदों में रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 21,000 युवाओं का सफल सेवायोजन हुआ। यह दिन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।

समन्वित मॉडल की ताकतः उद्योगों की मांग से जोड़ा कौशल

योगी सरकार की सबसे बड़ी सफलता यह है कि कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा गया है। प्रशिक्षण पूरा होते ही युवा सीधे रोजगार पा रहे हैं। राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में हम उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकसित कर रहे हैं। इससे स्थायी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन हो रहा है।'

यह मॉडल न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर वन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। पलायन रोकने में यह योजना क्रांतिकारी साबित हो रही है। ग्रामीण युवा अब गांव में ही नौकरी पाकर परिवार के साथ रह रहे हैं।

2026 के मेलेः नई उम्मीद, नई शुरूआत

जनवरी 2026 में होने वाले 5 मंडल स्तरीय मेले युवाओं के लिए वरदान साबित होंगे। बड़ी कंपनियां भाग लेकर मौके पर चयन करेंगी। यह मेले न केवल रोजगार देंगे, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास जगाएंगे। योगी सरकार की यह पहल साबित करती है कि सही नीति और मजबूत इरादे से असंभव कुछ नहीं।

उत्तर प्रदेश आज देश में रोजगार सृजन का मॉडल बन रहा है। योगी सरकार की यह शानदार उपलब्धि लाखों परिवारों की खुशहाली का आधार है। युवा अब सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें साकार कर रहे हैं। यह बदलाव उत्तर प्रदेश की नई पहचान है—आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध।

# परिवार के बीच दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क में राहत, अब व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियां भी शामिल

**योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य में पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण होगा आसान**

**पारिवारिक सदस्यों को दान दी गई संपत्ति पर देय होगा अधिकतम ₹5,000 स्टाम्प शुल्क**

**व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर मिली राहत, शहरी और गांव सभी जगह होगा लागू**

लखनऊ, 6 जनवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल संपत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में दी जा रही छूट के दायरे को और व्यापक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से अब पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दान विलेखों पर संपत्ति के मूल्य के अनुसार हस्तांतरण पत्र (कन्वेयंस डीड) की भांति स्टाम्प शुल्क देय होता है, जबकि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार अचल संपत्ति के दान विलेख का पंजीकरण अनिवार्य है।

₹5,000 तक सीमित है स्टाम्प शुल्क

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 की 3 अगस्त 2023 की अधिसूचना के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी कि यदि अचल संपत्ति का दान परिवार के सदस्यों के पक्ष में किया जाता है तो स्टाम्प शुल्क में छूट देते हुए अधिकतम ₹5,000 ही लिया जाएगा। यह छूट अब तक केवल कृष्य एवं आवासीय संपत्तियों तक सीमित थी। योगी कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इस छूट को पारिवारिक सदस्यों के मध्य व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे परिवारों के बीच संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और कम खचीर्ली हो जाएगी।

शहरी और ग्रामीण सभी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर मिलेगी राहत

प्रदेश के स्टांप तथा पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि 2022 से पहले तक परिवार के रिश्ते में यदि कोई प्रॉपर्टी देता था तो पूरे सर्किल रेट के बराबर स्टाम्प शुक्ल देना पड़ता था। 2022 में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तय हुआ कि पारिवारिक रिश्तों में यदि कोई प्रॉपर्टी दान की जाती है तो उस पर फिक्स्ड 5 हजार रुपए स्टांप लगेगा। लेकिन यह दान केवल आवासीय और कृषि पर लागू था, लेकिन अब यह नियम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी लागू कर दिया गया है। शहर के अंदर अब तक यह 7 प्रतिशत और गांवों में 5 प्रतिशत था, लेकिन अब गांव या शहर कहीं भी आपको केवल 5 हजार रुपए ही भुगतान करना है।

प्रावधानों में और स्पष्टता

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, पूर्व में जारी अधिसूचना में उल्लिखित संबंधियों की परिभाषा एवं अन्य प्रावधानों को भी और अधिक स्पष्ट किया गया है, जिससे नियमों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। यह छूट संबंधित अधिसूचना के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले को आम जनता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पारिवारिक संपत्ति के वैधानिक हस्तांतरण को प्रोत्साहन मिलेगा और विवादों में भी कमी आएगी।

## कुशीनगर और झांसी में नए उप निबंधक कार्यालय भवनों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत कैबिनेट ने जनपद कुशीनगर की तहसील कप्तानगंज में उप निबंधक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ग्राम बसहिया उर्फ कप्तानगंज स्थित तहसील परिसर की भूमि में से 0.0920 हेक्टेयर (920 वर्गमीटर) भूमि को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्तमान में उप निबंधक कार्यालय जीर्ण-शीर्ण भवन में संचालित है, जिसे ध्वस्त कर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने झांसी में उप निबंधक कार्यालय सदर एवं अभिलेखागार के निर्माण हेतु पुरानी तहसील परिसर, मौजा झांसी खास स्थित आराजी संख्या 3035 में से 0.0638 हेक्टेयर (638 वर्गमीटर) भूमि को राजस्व विभाग से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को आवंटित/हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की। दोनों ही मामलों में भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, अतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टाम्प शुल्क से तथा रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।

# यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 2.89 करोड़ नाम कटे, 12.55 करोड़ वोटर बचे

लखनऊ। (जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस ड्राफ्ट सूची में कुल 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 18 प्रतिशत है। इनमें 46.23 लाख मृत मतदाता, 2.17 करोड़ स्थानांतरित हो चुके लोग और 25.47 लाख डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। एसआईआर से पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, जो अब घटकर 12.55 करोड़ रह गए हैं। प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (रक्क्र) के अंतर्गत मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेसवार्ता में बताया।

जिला स्तर पर देखें तो राजधानी लखनऊ में सबसे अधिक करीब 12 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से कटे हैं, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95 हजार नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी मतदाता आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। जिन मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। नवदीप रिणवा ने बताया कि नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा। इसके अलावा नाम में सुधार या निवास परिवर्तन के

# लखनऊ मेट्रो की सतर्कता से 9 वर्षीय बच्ची सुरक्षित मिली: परिजनों से बिछड़ने के बाद त्वरित कार्रवाई से परिवार को सौंपी गई

**लखनऊ मेट्रो में खोई 9 वर्षीय बच्ची को सुरक्षित परिवार को सौंपते कर्मचारी**

**लखनऊ मेट्रो कर्मचारी बच्ची को सुरक्षित रूप से परिवार के सुपुर्द करते हुए**

लखनऊ, (जीएनएस)।

लखनऊ मेट्रो ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट सतर्कता, संवेदनशीलता और मानवीय जिम्मेदारी का परिचय देते हुए परिजनों से बिछड़ी 9 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची को सुरक्षित रूप से उसके परिवार तक पहुंचाया। यह घटना लखनऊ मेट्रो की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों की त्वरित प्रतिक्रिया का जीता-जागता उदाहरण है, जो यात्रियों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दशार्ती है। योगी सरकार के कुशल नेतृत्व में लखनऊ मेट्रो लगातार जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सेवा प्रदान कर रही है, जिससे शहरवासियों में विश्वास और बढ़ रहा है।

घटना का विवरणः लेखराज मेट्रो स्टेशन पर बिछड़ी बच्ची

घटना 4 जनवरी 2026 की शाम करीब 6 बजे की है, जब लेखराज मेट्रो स्टेशन पर 9 वर्षीय बच्ची अपने परिजनों से बिछड़ गई। स्टेशन पर तैनात मेट्रो कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और बच्ची को सुरक्षित संरक्षण में ले लिया। बच्ची को अलग-थलग देखते ही कर्मचारियों ने उसे स्टेशन कंट्रोल रूम में ले जाकर आवश्यक देखभाल की और स्टेशन कंट्रोलर को सूचना दी।

स्टेशन कंट्रोलर ने बच्ची से पूछताछ की, उसकी जानकारी सत्यापित की और मिली जानकारी के आधार पर लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र निवासी बच्ची की बहन से संपर्क स्थापित किया। सभी औपचारिकताओं और पहचान सत्यापन के बाद शाम करीब 6:30 बजे बच्ची को सकुशल

उसकी बहन के सुपुर्द कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कोई देरी नहीं हुई और बच्ची पूरी तरह सुरक्षित रही।

परिजनों की सराहनाः मेट्रो कर्मचारियों का आभार

परिजनों ने लखनऊ मेट्रो के कर्मचारियों की तत्परता, सहयोगात्मक रवैये और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मेट्रो की त्वरित कार्रवाई के कारण उनकी बच्ची सुरक्षित मिली, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती थी। परिजनों ने मेट्रो प्रबंधन को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह घटना मेट्रो की विश्वसनीयता को और मजबूत करती है।

यूपीएमआरसी प्रबंध निदेशक का बयानः सुरक्षा सर्वोपरि

इस घटना पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक श्री सुशील कुमार ने कहा, 'लखनऊ मेट्रो न केवल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, बल्कि सामाजिक दायित्वों के प्रति भी पूरी तरह सजग एवं प्रतिबद्ध है। हमारी टीम हर स्थिति में संवेदनशीलता के साथ कार्य करती है और आगे भी इसी भावना के साथ सेवाएं प्रदान करती रहेगी।' उनका यह बयान मेट्रो की जन-केंद्रित नीति को रेखांकित करता है।

लखनऊ मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्थाः जनता के हित में मजबूत कदम

लखनऊ मेट्रो योगी सरकार के प्रयासों से लगातार उन्नत हो रही है। यहां सीसीटीवी कैमरे, महिला हेल्पडेस्क, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, आपातकालीन बटन और प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात हैं। मेट्रो में खोए हुए बच्चों, वृद्धों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू हैं, जिसके तहत ऐसी घटनाओं में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

हाल के वर्षों में मेट्रो ने कई बार ऐसी घटनाओं में सफलता प्राप्त की है, जो यात्रियों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाती है। यह घटना भी मेट्रो की सतर्कता का प्रमाण है, जिससे लाखों यात्रियों को लाभ मिल रहा है।

प्रमुख तथ्य एक नजर में

विवरण जानकारी

घटना तिथि 4 जनवरी 2026 (शाम करीब 6 बजे)

स्थान लेखराज मेट्रो स्टेशन, लखनऊ

बच्ची की उम्र 9 वर्ष

निवास स्थान ब ा ी के ट ी, लखनऊ

कार्रवाई समय 30 मिनट के भीतर परिवार को सौंपी

जिम्मेदार विभाग उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन

यह तालिका घटना के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करती है।

सरकार के प्रयासः जनसुरक्षा में अग्रणी भूमिका

योगी आदित्यनाथ सरकार सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने पर जोर दे रही है। लखनऊ मेट्रो में लगातार अपग्रेडेशन, नई ट्रेनें, स्टेशनों का विस्तार और सुरक्षा उपकरणों की स्थापना हो रही है। इन प्रयासों से न केवल यात्रा सुगम हुई है, बल्कि महिलाओं, बच्चों और आमजन की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। मेट्रो का यह मानवीय पक्ष जनता के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दशार्ता है।

निष्कर्षः मेट्रो की संवेदनशीलता से मजबूत होगा विश्वास

लखनऊ मेट्रो की इस त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सार्वजनिक परिवहन केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा और विश्वास का केंद्र भी है। 9 वर्षीय बच्ची का सुरक्षित मिलना परिजनों के लिए राहत की बात है और मेट्रो कर्मचारियों के लिए गर्व का विषय। योगी सरकार के नेतृत्व में लखनऊ मेट्रो ऐसी घटनाओं में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाती रहेगी, जिससे शहर की जनता को सुरक्षित और बेहतर सेवाएं मिलती रहेंगी। यह घटना हमें सिखाती है कि सतर्कता और संवेदनशीलता से कितनी छोटी-सी गलती भी बड़ी त्रासदी बनने से बच सकती है।

# सुशासन, सुरक्षा और संस्कृति का संदेश लेकर चली 'लखनऊ दर्शन' वाली बस

**पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर 1090 चौराहे से बस को किया रवाना**

**इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस से पर्यटकों को कराया जाएगा लखनऊ का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक भ्रमण**

रिपोर्ट आशीष तिवारी (ब्यूरोचीफ)

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ में पर्यटन को नई पहचान देने की एक महत्वपूर्ण शुरूआत हुई। 'लखनऊ दर्शन' के नाम से इस विशेष बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने महिला सशक्तिकरण के प्रतीक 1090 चौराहे से रवाना किया। अब पर्यटक लखनऊ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों का भ्रमण करने के साथ ही सरकार के सामाजिक सरोकारों से भी सीधे तौर पर रूबरू होंगे। 'लखनऊ दर्शन' के तहत पर्यटकों के लिए दो आकर्षक टूर पैकेज तैयार किए गए हैं। पहला टूर सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होगा, जबकि दूसरा टूर शाम 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा। इस पैकेज का किराया 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 400 रुपये और 12 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों के लिए 500 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। टूर पैकेज में जलपान की सुविधा भी शामिल है। पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट ४स्र२३ि्.ल्ल पर की जा सकती है। 'लखनऊ दर्शन' के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पर्यटन को सामाजिक चेतना, सुरक्षा और सुशासन के संदेश के साथ जोड़कर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाइयों तक ले जाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

# पीलीभीत में 1654 मतदेय स्थलों पर विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन

ब्यूरो रिपोर्टः

पीलीभीत, 6 जनवरी 2026: जनपद पीलीभीत में लोकतंत्र की मजबूती को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 6 जनवरी 2025 को जिले के समस्त 1654 मतदेय स्थलों पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया। यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों के अनुरूप संपन्न हुई, जिससे मतदाता सूची में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हुई है।

इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले भर में फैले 1654 मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की योग्यता का गहन परीक्षण किया गया। इसमें नामों के जोड़ने, हटाने, संशोधन और स्थानांतरण जैसे कार्य शामिल थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में चली इस प्रक्रिया में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और अन्य निर्वाचन कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। आलेख्य प्रकाशन के माध्यम से अब मतदाता अपनी जानकारी की जांच कर सकते हैं और यदि कोई त्रुटि हो तो तत्काल सुधार करा सकते हैं।

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस पुनरीक्षण से मतदाता सूची में हजारों नए मतदाताओं का नाम जुड़ा है, खासकर युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियों को मजबूत बनाएगी। निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है कि सभी मतदाता 25 जनवरी 2026 तक अंतिम प्रकाशन से पहले अपनी फॉर्म-6, फॉर्म-7, फॉर्म-8 आदि के माध्यम से नामावली में संशोधन कराएं।

यह अभियान न केवल मतदाता सूची को अद्यतन रखेगा, बल्कि फर्जी वोटिंग और डुप्लिकेट एंट्रीज को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा। जिला प्रशासन ने मतदेय स्थलों पर सूचनाबोर्ड लगाने और मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन जांच की सुविधा भी प्रदान की है। पीलीभीत जिले के निवासियों से अपेक्षा है कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

# पीलीभीतः डीआईजी/एसपी के निर्देशन में सड़क सुरक्षा माह में सघन चेकिंग, 176 चालान काटे, 1.98 लाख वसूले

(जीएनएस)।

पीलीभीत, DIG/SP के सख्त निदेशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा माह के तहत जनपदीय एवं यातायात पुलिस ने वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में कुल 176 वाहनों के खिलाफ चालान जारी किए गए, जिन पर 1,98,000 रुपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।

अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने मुख्य मार्गों जैसे तनाकपुर रोड, पुरान शहर, बाजार क्षेत्रों एवं हाईवे पर विशेष नजर रखी। ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट, तेज गति, ट्रिपल राइडिंग आदि उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। साथ ही, मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटवाकर यातायात को सुगम बनाया गया, जिससे जाम की स्थिति में काफी राहत मिली।

यातायात पुलिस ने राहगीरों एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, पंपलेट वितरण एवं मौखिक समझाइश दी। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य करने तथा कार चालकों को सीट बेल्ट बांधने पर जोर दिया गया। एसपी ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य दुर्घटनाओं को शून्य करना है। जनपद में हालिया दिनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखते हुए यह अभियान और सशक्त बनाया जाएगा।

अभियान में एसपी सदर बाजार, तहसील क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में सक्रिय रहीं। आने वाले दिनों में स्कूल-कॉलेजों के निकट विशेष चेकिंग एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आमजन से अपील की गई है कि यातायात नियमों का पालन करें ताकि कोई अनहोनी न घटे।

## माघ मेला 2026 से पूर्व फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फेज-02 का भव्य शुभारंभ

(जीएनएस)।

**प्रयागराज को मिला जल-पर्यटन और मनोरंजन का नया आयाम**

प्रयागराज। माघ मेला 2026 के दृष्टिगत प्रयागराज में पर्यटन एवं मनोरंजन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के फेजझ्र02 का आज भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त श्रीमती सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा, उत्तर प्रदेश के पुलिस आयुक्त श्री जोगेंद्र कुमार एवं नगर आयुक्त श्री सीलम साईं तेजा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फेजझ्र02 का उद्घाटन किया।

प्रयागराज स्मार्ट सिटी प्रा.लि. नगर निगम प्रयागराज द्वारा विकसित इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को नए कलेवर में तैयार किया गया है।

## 20 वर्षीय युवक का शव घर के पीछे स्थित आम की बाग मे लटकता मिला

मोहित हिंदू जिला संवाददाता

मसौली बाराबंकी। सोमवार की देर शाम घर से निकले एक 20 वर्षीय युवक का शव घर के पीछे स्थित आम की बाग मे लटकता मिला घटना की जानकारी मिलते ही घर एव गाव मे कोहराम मच गया सूचना पर पहुंची सफदरगंज पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर भवानीपुर निवासी महेश दीक्षित का 20 वर्षीय पुत्र शौरभ दीक्षित सोमवार की देर शाम घर से निकला था जो देर रात्रि तक परिजनो ने तलाश की परन्तु शौरभ का पता नहीं चला मंगलवार को परिजन युवक की तलाश कर रहे थे कि ग्रामीणों की नजर घर से थोड़ी दूरी पर स्थित आम की बाग मे लगे एक चिलवल के पेड़ मे लटकती मिली। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव की शीनख्त करते हुए पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ।

# धनारा घाट माघ मेला स्थल का निरीक्षण, शांति-व्यवस्था के लिए सख्त निर्देश

(जीएनएस)।

पीलीभीत। DIG/SP पीलीभीत के निर्देशन में एडिशनल एसपी पीलीभीत द्वारा थाना हजारा क्षेत्रांतर्गत धनारा घाट पर प्रस्तावित माघ मेला स्थल का निरीक्षण किया गया।

इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मेले के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करना था।

एडिशनल एसपी ने चिन्हित स्थान का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एडिशनल एसपी ने थाना प्रभारी हजारा, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की

उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु पार्किंग व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण तथा आपातकालीन सेवाओं की पुख्ता तैयारी पर जोर दिया।

विशेष रूप से नदी घाट क्षेत्र में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए लाइफ जैकेट, रेस्क्यू टीम तथा चेतावनी चिन्ह लगाने के निर्देश दिए गए।

साथ ही, अवैध शराब बिक्री, जुआ तथा अन्य असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने हेतु विशेष निगरानी टीम गठित करने के आदेश जारी किए।

एडिशनल एसपी ने स्पष्ट किया कि माघ मेला धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसलिए किसी भी प्रकार की छूट नहीं बरती जाएगी।

मेले से पूर्व सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा तथा सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी तथा फ्लैग मार्च की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

स्थानीय लोगों से भी अपील की गई कि वे मेले के दौरान सतर्क रहें तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें।इस पहल से क्षेत्रवासियों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ा है।

# बीसलपुर कोतवाली पुलिस की सतर्कताः शराब के 32 पाउच बरामद, दो शराब तस्कर गिरफ्तार

(जीएनएस)।

पीलीभीत, बीसलपुर। स्थानीय कोतवाली पुलिस ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए गांव परसिया के बरात घर के पास से दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे दोनों आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 32 शराब के पाउच बरामद हुए हैं। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है तथा बरामद शराब को सील कर दिया गया है। दोनों आरोपियों का चालान कर दिया गया है।

यह कार्रवाई कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम नियमित गश्त के दौरान परसिया गांव पहुंची थी, जहां बरात घर के आसपास संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दीं। जांच के दौरान गांव कासिमपुर निवासी गोविंद(उम्र 28 वर्ष) और गांव हाफिज नगर निवासी गजेंद्र पाल (उम्र 32 वर्ष) को रोका गया। उनकी तलाशी में अवैध शराब के 32 पाउच (कुल मात्रा लगभग 1.6 लीटर) मिले, जो बाजार मूल्य के हिसाब से हजारों रुपये के थे।

पुलिस ने बताया कि यह शराब बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बेची जा रही थी, जो क्षेत्र में शराबबंदी नियमों का उल्लंघन था। आरोपी स्थानीय स्तर पर तस्करी कर रहे थे और आसपास के गांवों में इसका वितरण कर रहे थे। आबकारी विभाग को सूचना दे दी गई है तथा आगे की पूछताछ में अन्य तस्करों का पदार्फाश होने की संभावना है। यह घटना क्षेत्रवासियों में पुलिस की सतर्कता को लेकर संतोष का विषय बनी हुई है।

कोतवाली प्रभारी ने अपील की है कि अवैध शराब तस्करी की सूचना देने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा तथा आमजन से सहयोग की अपेक्षा की है।

# विराट रुद्र महायज्ञ के दूसरे दिन प्रयागराज लहुरी (काशी) से पधारे

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। कस्बा मसौली स्थित बाबा राम शरण दास भगवत दास कुटी हनुमान मंदिर परिसर में चल रहे विराट रुद्र महायज्ञ के दूसरे दिन प्रयागराज लहुरी (काशी) से पधारे यज्ञ सम्राट स्वामी प्रमोदानन्द जी महाराज ने अपने सत्संग में मानव जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाला। महाराज जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथहि गावा। उन्होंने बताया कि मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है और जो व्यक्ति मुक्ति की कामना से संतों के चरणों में जाता है उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता। स्वामी जी ने आगे कहा कि भक्त के घर की तीन प्रमुख पहचान होती है। तुलसी सेवा, गौसेवा, और सालिकराम सेवा। जिन घरों में ये तीनों सेवाएं नियमित रूप से होती हैं, वहां अकाल मृत्यु का नहीं होती र। इसी क्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रामसिंह वर्मा (भुल्लन वर्मा), मंदिर समिति के अध्यक्ष मोहित वर्मा (हिंदू), सचिव राहुल ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों ने महाराज जी को जय श्रीराम लिखे पटके एवं माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर के पुजारी रामलाल दास सहित समस्त ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सत्संग का लाभ लिया।

# विवादित सचिव को संरक्षण देने के आरोपों में घिरे डीपीआरओ, भाकियू भानु ने उठाए सवाल

(जीएनएस)।

पूरनपुर,पीलीभीत ।ग्राम पंचायत शेरपुर कला से जुड़े विवाद में अब जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) पर गंभीर आरोप लगने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु ने डीपीआरओ पर आरोप लगाया है कि वह ग्राम पंचायत में तैनात विवादित सचिव को संरक्षण दे रहे हैं, जिसके चलते बार-बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। संगठन का कहना है कि यह मामला केवल एक पंचायत तक सीमित नहीं, बल्कि पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है।भाकियू भानु के पदाधिकारियों के अनुसार ग्राम पंचायत शेरपुर कला के सभी पंचायत सदस्यों ने 30 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी को शपथ पत्र सौंपकर ग्राम पंचायत अधिकारी पर अभद्र व्यवहार, पंचायत सदस्यों की अनदेखी और विकास कार्यों में मनमानी के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप है कि सचिव पंचायत की बैठकों में सहयोग नहीं करता और सदस्यों के प्रस्तावों को जानबूझकर दबाया जाता है। इसके बावजूद डीपीआरओ स्तर से कोई विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की गई।संगठन का दावा है कि सचिव अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पंचायत में तैनात सफाई कर्मियों के माध्यम से अवैध उगाही करवा रहा है। मनमाने ढंग से सफाई कार्य कराए जा रहे हैं और भुगतान में भी अनियमितता बरती जा रही है। इन सभी मामलों की लिखित शिकायतें जिला प्रशासन, डीपीआरओ और खंड विकास अधिकारी को दी गईं, लेकिन हर स्तर पर फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी हैं।31 दिसंबर 2025 को पंचायत सदस्यों ने ग्राम प्रधान को पत्र देकर

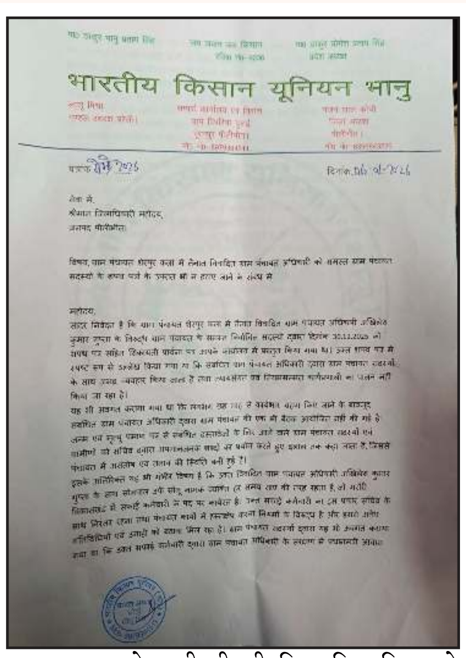
भारतीय किसान यूनियन भानु

चेतावनी दी थी कि यदि सचिव को नहीं हटाया गया तो विकास कार्य ठप कर दिए जाएंगे। इसके बाद 1 जनवरी 2026 को ग्राम प्रधान ने भी जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सचिव को हटाने की मांग की। 4 जनवरी को खंड विकास अधिकारी पूरनपुर को भी पत्र सौंपा गया, लेकिन कार्रवाई न होने से पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है।

भारतीय किसान यूनियन भानु ने सीधे तौर पर डीपीआरओ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विवादित सचिव को संरक्षण देने के कारण ही अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। संगठन का कहना है कि यदि डीपीआरओ निष्पक्ष होते तो जांच कराकर सचिव को हटाया जा सकता था, जिससे पंचायत में शांति व्यवस्था बनी रहती।

भाकियू भानु ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 10 जनवरी 2026 को ब्लॉक पूरनपुर में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद प्रयागराज में संगठन के शिविर से लौटकर जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी प्रशासन की

## वरिष्ठ अधिवक्ता कन्हैयालाल गौतम का जन्मदिन हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया

वरिष्ठ अधिवक्ता कन्हैयालाल गौतम अधिवक्ताओं के अत्यंत शुभचिंतक हैं:- अधिवक्ता अनुज बाजपेई

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग क्षेत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विधि जगत की प्रतिष्ठित हस्ती कन्हैयालाल गौतम का जन्मदिन आज लखनऊ बार एसोसिएशन के हाल में हर्ष, उल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता, साथीगण तथा उनके शुभचिंतक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जन्मदिन की शुभकामनाएं के नारों से पूरा हाल गूंज उठा। समारोह के दौरान लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष (मध्य) पद के प्रत्याशी अधिवक्ता अनुज बाजपेई ने कन्हैयालाल गौतम को भव्य माला पहनाकर सम्मानित किया तथा भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्मृति-चिह्न स्वरूप भेंट कर उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं के बीच मिठाइयों का वितरण भी किया गया अधिवक्ता अनुज बाजपेई ने अपने संबोधन में गौतम जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अधिवक्ताओं के अत्यंत शुभचिंतक हैं। वे सदैव युवा अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन करते रहते हैं तथा उनके हितों के संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

उनका दीर्घ अनुभव, सरल स्वभाव और सहयोगी भावना बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों के लिए प्रेरणास्रोत है कार्यक्रम के दौरान अन्य अधिवक्ताओं ने भी कन्हैयालाल गौतम के न्यायप्रिय व्यक्तित्व, विधि क्षेत्र में उनके दीर्घकालीन योगदान एवं बार एसोसिएशन के प्रति उनकी निष्ठा की सराहना की। इस अवसर पर केक काटा गया तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर सभी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। नवीन कुमार ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में अधिवक्ता रंजीत कुमार शर्मा, नरेंद्र कुमार साहू, ऐश्वर्य पांडे, काशान अंसारी, अंजलि कटियार, वसीमा खान सहित अनेकों अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। समारोह में आत्मीयता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा। उपस्थित सभी लोगों ने श्री गौतम के उत्तम स्वास्थ्य, दीघार्यु एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

# मिशन शक्ति 5 के तहत घुंघचाई पुलिस ने महिलाओं-बालिकाओं को किया सशक्तिकरण जागरूक

(जीएनएस)।

पीलीभीत। DIG/SP पीलीभीत के सख्त निदेशों पर मिशन शक्ति 5 अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए घुंघचाई थाना पुलिस ने थाना क्षेत्रांतर्गत सक्रिय भ्रमण शुरू किया। इस विशेष अभियान में पुलिस टीम ने गांव-गांव जाकर महिलाओं व बालिकाओं को महिला संबंधी अपराधों तथा साइबर अपराधों से बचाव के लिए विस्तृत जागरूकता फैलाई।

घुंघचाई थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों जैसे घुंघचाई, आसपास के मोहल्लों और स्कूलों का दौरा किया। यहां पहुंचकर उन्होंने महिलाओं व बालिकाओं को संबोधित करते हुए बताया कि दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन शोषण जैसे अपराधों से बचने के लिए तत्काल 1090 वुमन पावर लाइन या 112 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही, साइबर अपराधों जैसे फर्जी कॉल, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग से सावधान रहने की सलाह दी गई।

पुलिस टीम ने जागरूकता सत्रों में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो क्लिप्स और पर्चे बांटे। उन्होंने महिलाओं को सिखाया कि संदिग्ध कॉल आने पर कभी पर्सनल जानकारी न दें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें तथा परिवार के साथ मिलकर सतर्क रहें। अभियान के दौरान दर्जनों महिलाओं व बालिकाओं ने पुलिस की सराहना की और कहा कि ऐसी जागरूकता से वे आत्मरक्षा के प्रति अधिक सजग हो गई हैं।

मिशन शक्ति 5 उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और अपराधमुक्त समाज गढ़ने पर केंद्रित है। उक्र्रढ पीलीभीत ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाया जाए। घुंघचाई पुलिस ने प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि भविष्य में भी नियमित भ्रमण जारी रहेंगे।